चुनावी शोर में दबा गन्ना किसानों का भुगतान

यूपी के किसानों का दस हजार करोड़ रुपये से अधिक का बकाया

- राज्य की सपा और केंद्र की संप्रग के खिलाफ किसान गोलबंद
- रंगराजन सिफारिशें लागू करने का खामियाजा भुगत रहे किसान

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, थानाभवन (शामली)

बड़ा मुद्दा

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में गन्ना और जाति जैसे मुद्दे अहम भूमिका निभाने वाले थे। लेकिन दंगे के बाद बदली हुई परिस्थितियों में किसानों के जीवनयापन से जुड़ा गन्ना भुगतान का मसला चुनावी शोर में कहीं खो सा गया है। जिम्मेदार राजनीतिक दलों की इस मामले में चुप्पी किसानों को हैरान कर रही है। यही वजह है कि इस मुद्दे ने किसानों को प्रदेश की सत्तारुढ़ सपा सरकार और केंद्र की संप्रग सरकार के खिलाफ गोलबंद कर दिया है।

गन्ना क्षेत्र से ही संसद पहुंचने वाले चौधरी अजित सिंह के रालोद को लेकर भी यहां के लोगों में गुस्सा है। बजाज शुगर मिल में साहब सिंह ने गन्ना बेचा है, जिसका आठ-नौ लाख रुपये बकाया हो गया है। बकाया बढ़ने से हलकान गन्ना किसानों को बेटियों की शादी की तारीख तक आगे खिसकानी पड़ रही है। एक खास बात यह है कि पिछले साल के 280 रुपये प्रति क्विंटल से बीस रुपये कम का भुगतान हो रहा है।

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने गन्ना सत्र शुरू होने से पहले ही राज्य सरकार और किसानों को चेताया था कि मार्च के आखिर तक गन्ना बकाया भुगतान दस हजार करोड़ रुपये हो जाएगा। इस्मा के मुताबिक, अब तक 10,500 करोड़ रुपये की बकायेदारी हो गई है।

गन्ना किसानों को लुभाने के लिए एक ओर तो राज्य सरकार ने चीनी उद्योग को कई तरह की रियायतें देकर लगभग 6600 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया था। दूसरी ओर चौधरी अजित सिंह की सदस्यता वाली केंद्र सरकार की कमेटी ने चीनी मिलों को ब्याज मुक्त धनराशि की व्यवस्था की थी। इसमें उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के हिस्से में लगभग दो हजार करोड़ रुपये आए थे। हैरानी की बात यह है कि इतनी मदद मिलने के बाद भी किसानों को भुगतान के लाले पड़े हुए हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चलते चुनाव में यह मुद्दा भी लगभग गौण हो गया है।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दावे को भी चीनी उद्योग ने ठेंगा दिखा दिया है। अखिलेश ने गन्ना किसानों से कहा था कि मिलों में पेराई बंद होने से पहले ही सभी बकाया भुगतान कर दिया जाएगा, वह भी 280 रुपये प्रति क्विंटल की दर से। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। चुनाव के ऐन दौर में भुगतान अटकने से हलकान गन्ना किसानों का गुस्सा भी बढ़ने लगा है, जिसका विपरीत प्रभाव समाजवादी पार्टी की चुनावी सेहत पर पड़ सकता है। इस्मा और केंद्र की मिलीभगत के चलते रंगराजन समिति की सिफारिशों को लागू करना अब भारी पड़ रहा है, जिसका खामियाजा मिलों के बजाय गन्ना किसानों को भुगतना पड़ रहा है।

हरियाणा के रहमोकरम पर पश्चिमी यूपी

विशेष संवाददाता, शामली : आने जाने के लिए रास्ता, सेहत का इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों तक के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को हर रोज हरियाणा के रहमोकरम पर रहना पड़ता है। बड़ी तो दूर छोटी-मोटी जरूरतों के लिए भी हरियाणा का मुंह ताकना पड़ता है। खाद, बीज और डीजल के लिए हरियाणा जाना होता है। इतना ही नहीं कृषि उपज बेचने के लिए वहीं की मंडियों की शरण लेनी पड़ती है। बिगड़ी कानून व्यवस्था से जूझते और सांप्रदायिक तनावों के बावजूद यहां की बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे लोकसभा चुनावों के शोर में दब गए हैं।

राजधानी दिल्ली से चलकर शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जाना है तो सीधे रास्ते दिल्ली-सहारनपुर रोड से नहीं जाया जा सकता है। उस सड़क की हालत बेहद खस्ता है। लिहाजा दिल्ली से सोनीपत, पानीपत और करनाल के रास्ते ही यहां पहुंचना संभव है। तकरीबन 50 से 60 किमी अतिरिक्त चलना पड़ता है। सरे सीजन के दौरान उत्तर प्रदेश में फसलों के उन्नत व प्रमाणित बीज और जरूरी खादों की आपूर्ति नहीं हो पाती है। इन हालातों में किसानों को समय पर बीज व खाद की जरूरत हरियाणा से लाकर पूरी करनी पड़ती है। सस्ता डीजल भी यमुना पार कर पराये राज्य से लाना पड़ता है। गुड़ खाड़सारी कारोबार के लिए विश्व क्षितिज पर अपनी पहचान बनाने वाले इस क्षेत्र में सड़कें तो हैं, लेकिन मरम्मत के अभाव में इतनी खराब हैं कि उन पर चलना दूभर है। शासन की अनदेखी से यहां की सड़कों की मरम्मत तक नहीं हो पाई है। शामली से सीधे दिल्ली निकलने के लिए सहारनपुर-दिल्ली रोड पकड़ना आफत मोल लेने के बराबर है।

राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुधीर का कहना है कि राजनीतिक दलों ने जातीय व सांप्रदायिक समीकरणों के आधार पर चुनाव जीते और हारे हैं। राजनीति के इस खेल में आधारभूत मुद्दों की जबर्दस्त अनदेखी हुई है।

दैनिक जागरण
5/4/14